side, the BSNL employees, who are behind this mission of Digital India, are suffering the most. I would urge the Government to take immediate steps so that their wages are paid and made up to date. Thank you.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Payment of arrears to the sugarcane farmers

श्री मोतीलाल वोरा (छत्तीसगढ़): माननीय सभापति महोदय, गन्ना किसानों का गन्ने का भुगतान चीनी मिलों द्वारा काफी लम्बे समय से नहीं किया जा रहा है। गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर देय बढ़ता ही जा रहा है और यह बढ़कर 20 हजार करोड़ से अधिक हो गया है। सरकार सीमांत और मध्यम किसानों को दो हजार रुपये साल में तीन बार देने की बात तो कर रही है, लेकिन जो किसानों की मेहनत का अपना पैसा है, उसे दिलाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है।

सभापति महोदय, चीनी मिलों ने सुझाव दिया है कि घरेलू बाजार में चीनी का मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये कर दिया जाए। इससे वे किसानों को उनके गन्ने का मूल्य भुगतान करने में सक्षम हो जाएंगे। यदि सरकार चीनी का मूल्य बढ़ाने के लिए तैयार हो, तो चीनी मिलों से यह गारण्टी ली जानी चाहिए कि वे चीनी का दाम 35 रुपये करने के बाद गन्ना उत्पादकों का सारा भुगतान अविलम्ब कर देंगे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह गन्ना उत्पादकों का भुगतान अविलम्ब कराने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए।

Deprivation of reservation due to wrong pronunciation of various SCs/STs

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से जो जाति उच्चारण के बदलाव की वजह से जनजाति के संवैधानिक अधिकार से वंचित रह रही है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो सरकार का अभिनंदन करना चाहूंगा कि बजट में घूमंतू/अर्धघुमंतू यानी DTNT और NT के लिए एक वेलफेयर बोर्ड सरकार ने स्थापित किया है, जिसका फायदा सभी समुदायों को होगा, जो DTNT और NT हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक

और गंभीर समस्या है, जिसमें सिर्फ नाम के उच्चारण में फर्क होने से, लिखते समय बहुत सारी जनजातियों और जातियों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है, जैसे कि हलबा/हलबी में, हलबा का उच्चारण हलबी की तरह से होता है। इसी तरह धनगर और धनगड का है, जिससे हम हिन्दी में धनगड कहते हैं, "र" का उच्चारण "ड" होता है। इसी तरह से गोंडगोवारी (गोंड, गोवारी) के बीच में कॉमा न होने की वजह से उनको अभी तक आरक्षण का संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। महोदय, यह सिर्फ एक-दो स्टेट्स में ही नहीं है, बल्कि शेफर्ड कम्युनिटी धनगर और धनगड का मामला एमपी, यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बाकी सभी स्टेट्स में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धनगर का जो आरक्षण का मुद्दा था, उसके संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में लिखा था कि इसके आरक्षण पर हम अमल करेंगे, लेकिन यह अमल आज तक नहीं हुआ। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में बिल लाए और उसे पारित करे, ताकि चुनावी घोषणापत्र में जो वायदा महाराष्ट्र सरकार ने किया था, उसे पूरा किया जा सके और इन जनजातियों का जो अधिकार है, जिससे वे अभी तक वंचित हैं, वह उन्हें मिल सके।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

Constitution of Wage Board for working journalists

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Mr. Chairman, Sir, it is a matter of serious concern that 16 years have passed since the last Wage Board for working journalists and other newspaper employees was constituted. The stipulation is that a Wage Board must be constituted every five years to recommend revision in the wages of journalists and employees of newspaper industry, which has not been done so far.

Another thing is that television is a powerful segment of media industry in the country today. The industry employs thousands of journalist and non-journalist employees across the country, but they have not been covered under the Working Journalists and